बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 123 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 24 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

कांग्रेस नेता की कृष्ण हरि की गाड़ी में मिले टीशर्ट-पोस्टर, पांचवां आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली । दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी और यूथ कांग्रेस के नेता कृष्ण हरि की गाड़ी बरामद कर ली है। इस कार से टी शर्ट और पोस्टर भी मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने यूथ कांग्रेस के एक और प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार लिया है। ग्वालियर से जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। इस घटना के सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई यह पांचवीं गिरफ्तारी है। इस मामले में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने पहले ही प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार चार आरोपियों को पांच दिन की कस्टडी में भेजा था। एआई इंपैक्ट समिट में शुक्रवार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की भारत टैक्सी के ड्राइवरों से खास बातचीत

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत टैक्सी के ड्राइवरों के साथ संवाद किया। इन ड्राइवरों को सम्मानपूर्वक सारथी नाम दिया गया है। अमित शाह के साथ इस विशेष संवाद को मंत्री के ऑफिशियल यू-ट्यूब चैनल पर प्रसारित किया गया । इस कार्यक्रम में उन्होंने टैक्सी चालकों के अनुभव सुने, उनकी समस्याएं जानीं और सहकारिता आधारित इस नए मोबिलिटी मॉडल के भविष्य के विजन पर चर्चा की। सारथी ही मालिक की अवधारणा- अमित शाह ने संवाद के दौरान स्पष्ट किया कि भारत टैक्सी का मुख्य उद्देश्य ड्राइवरों को केवल कर्मचारी तक सीमित न रखकर उन्हें व्यवसाय का मालिक बनाना है। मुनाफे का सीधा लाभ- विदेशी फंडेड प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स (जैसे ओला, उबर आदि) के विपरीत, भारत टैक्सी जीरो-कमीशन और सर्ज-फ्री प्राइसिंग मॉडल पर काम करती है। मंत्री ने बताया कि कमाई का 80% हिस्सा सीधे ड्राइवरों के बैंक खाते में जाएगा जबकि 20% हिस्सा प्लेटफॉर्म के विस्तार के लिए रिजर्व रखा जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार का लक्ष्य- वर्तमान में इसके पायलट प्रोजेक्ट को दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। अमित शाह ने घोषणा की है कि अगले 3 वर्षों के भीतर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत टैक्सी को पूरे देश में रोलआउट किया जाएगा।

क्या है भारत टैक्सी?

भारत टैक्सी देश की पहली सहकारिता-आधारित कैब सेवा है। इसे हाल ही में 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। इसे अमूल, इफ्को, नेफेड और कृभको जैसी देश की शीर्ष 8 सहकारी संस्थाओं द्वारा मिलकर प्रमोट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आम लोगों को सस्ती व सुरक्षित राइड देना और कैब चालकों को शोषण मुक्त माहौल मुहैया कराना है।

सारथियों (ड्राइवरों) को मिलने वाली विशेष सुविधाएं

बीमा और सुरक्षा- भारत टैक्सी से जुड़ने वाले प्रत्येक सारथी को 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपये का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। सारथी दीदी पहल- महिला सशक्तिकरण और महिला यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सारथी दीदी पहल शुरू की गई है। इसके तहत महिला ड्राइवर (टू-व्हीलर) विशेष रूप से महिला यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगी। काम की स्वतंत्रता- ड्राइवरों पर कोई एक्सक्लूसिविटी क्लॉज नहीं थोपा गया है। वे स्वतंत्र रूप से इस एप के साथ-साथ अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी काम कर सकते हैं।

संवाद के दौरान ड्राइवरों ने अपनी दैनिक चुनौतियों, कमाई, एप पर अनुभव और अपेक्षाओं को मंत्री शाह के सामने रखा। अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का लक्ष्य ड्राइवरों की आय और गरिमा बढ़ाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार खुद टैक्सी सेवा नहीं चला रही है बल्कि सहकारी संस्था को बल दे रही है, जिसके मालिक ड्राइवर खुद हैं। ड्राइवरों को आश्वासन दिया कि प्लेटफॉर्म आगे भी उनके हितों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा। इसके अलावा समय-समय पर सुधार व नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। ड्राइवरों ने अपने अनुभव साझा किए। इनमें कई ड्राइवरों ने कहा कि इससे उन्हें पहले से अधिक स्वतंत्रता व आर्थिक लाभ मिला है। अमित शाह ने कहा कि अभी तक भारत टैक्सी में 2.5 लाख ड्राइवर इस सेवा में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।

अब आप सिर्फ ड्राइवर नहीं, बल्कि मालिक हैं

सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्राइवेट कैब कंपनियां सिर्फ अपने बड़े मालिकों की जेब भरती हैं। वहां आपकी मेहनत की कमाई का 30त हिस्सा वे लोग काट लेते थे और कमाई की कोई गारंटी भी नहीं होती थी। उन्होंने कहा, ÷हमारी सोच एकदम सीधी है- जो पसीना बहाए, असली मुनाफा भी उसी को मिले, किसी बड़े सेठ को नहीं। भारत टैक्सी भी अपने मालिकों को ही अमीर बनाना चाहती है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां आप ही इसके असली मालिक हैं÷।

मिलकर काम करने की ताकत ही सहकारिता है

अमित शाह ने समझाया, अगर आप सहकारिता का मतलब समझ लेंगे तो आपके सारे सवाल खुद ही खत्म हो जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि सबका मिलकर काम करना और जो भी कमाई हो उसकी बराबर हिस्सेदारी। अमूल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसे किसी बड़े सेठ ने नहीं बल्कि गुजरात की 36 लाख आम महिलाओं ने मिलकर खड़ा किया है। शुरुआत में इन महिलाओं ने सिर्फ 50-50 रुपये मिलाकर इसे शुरू किया था। धीरे-धीरे और लोग जुड़ते गए और आज यही कंपनी 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस कर रही है। यह साबित करता है कि जब लोग साथ आते हैं तो छोटी शुरुआत भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमूल से जुड़ी 25 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने एक साल में 1 करोड़ रुपये से यादा का दूध बेचा है। मैंने विभाग से कहा है कि इन महिलाओं के नाम वेबसाइट पर डालें ताकि सबको पता चले कि आम लोग मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण पर सख्त- कोयला आधारित उद्योगों को हटाने पर केंद्र से मांगा जवाब, 12 मार्च को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को कई अहम निर्देश दिए हैं और अलग-अलग मुद्दों पर जवाब तलब किया है। अदालत ने खास तौर पर कोयला आधारित उद्योगों, निर्माण और तोड़फोड़ के दौरान उड़ने वाली धूल और वाहनों के प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा है। नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में लगातार वायु गुणवत्ता की दिक्कत से निपटने के लिए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि वह कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के सुझावों के आधार पर 12 मार्च को गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे की जांच करेगी। इसने भवन निर्माण और तोड़-फोड़ की वजह से होने वाली धूल से निपटने के लिए सीएक्यूएम के सुझाए गए तरीकों पर सभी स्टेकहोल्डर्स से भी जवाब मांगा। पीठ ने इस सुझाव पर भी केंद्र से जवाब मांगा कि दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में कोई नया कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित न किया जाए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को सार्वजनिक नोटिस जारी कर एनसीआर में संचालित कोयला आधारित उद्योगों सहित सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया।इन नोटिसों को कोर्ट द्वारा भेजा गया नोटिस माना जाएगा और राज्यों को मिले फीडबैक की डिटेल देते हुए एक ÷एक्शन टेकन प्लान÷ जमा करने को कहा गया है। इसने केंद्र सरकार के मंत्रालयों को एनसीआर के अंदर कोयला-आधारित इंडस्ट्रीज को धीरे-धीरे खत्म करने के मकसद से एक संयुक्त प्रस्ताव जमा करने को कहा गया है। बेंच ने आदेश दिया, प्रस्ताव में सबसे पहले इंडस्ट्रीज की पहचान की जाएगी।

और यह तय किया जाएगा कि उनके लिए कौन से वैकल्पिक ईंधन स्रोत दिए जा सकते हैं। बेंच ने दिल्ली सरकार को सीएक्यूएम द्वारा सुझाए गए इन लॉन्ग-टर्म सॉल्यूशन को लागू करने के लिए एक खास एक्शन प्लान जमा करने का निर्देश दिया।बेंच ने कहा, कमीशन ने उन संबंधित एजेंसियों की पहचान की है जिनसे एक्शन लेने की उम्मीद है। इसलिए हम दिल्ली सरकार को इन उपायों को लागू करने के लिए एक प्रपोस्ड एक्शन प्लान जमा करने का निर्देश देते हैं। इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के चलने से प्रदूषण बढ़ने का सवाल भी उठा। बेंच ने कहा कि इसका परीक्षण किए जाने की जरूरत है। अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की है।

दिल्ली पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के पांच सदस्यों को दबोचा, यूके भेजी जाने वाली साइकोट्रोपिक टैबलेट जब्त

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस सिंडिकेट द्वारा यूके एक्सपोर्ट किए गए कंटेनर से करीब नौ करोड़ कीमत की 18,47,400 साइकोट्रोपिक टैबलेट जब्त की गई है। आरोपितों में एक विष्णु दत्त शर्मा ने कंटेनर से घरेलू सामान यूके एक्सपोर्ट करने पर उसमें ट्रामाडोल और अन्य प्रतिबंधित गोलियों के 32 डिब्बे छिपा दिए थे। सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने कंटेनर को पकड़ने के लिए कस्टम अधिकारियों के साथ समन्वय कर शिपमेंट यूके में वितरित नहीं होने दिया और उसे वापस भारत मंगवा लिया गया।

टी-थ्री टर्मिनल, मुंद्रा पोर्ट, गुजरात में कंटेनर के वापस पहुंचने पर उसे जब्त कर लिया गसा डीसीपी विक्रम सिंह के मुताबिक सात अक्टूबर को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने महक अपार्टमेंट, मदनपुर खादर एक्सटेंशन-एक, सरिता विहार से मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार कर लिया था। तलाशी में 54,000 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट (ट्रेकेन-100) (वजन-14.472 किलो) बरामद की गई। उससे पूछताछ और टेक्निकल सर्विलांस के दौरान, गैर-कानूनी फार्मास्यूटिकल नेटवर्क की सप्लाई चेन के बारे में पता चला। इसके बाद कंटेनर टी-3 टर्मिनल, मुंद्रा पोर्ट, गुजरात पर पहुंचकर पुलिस ने कस्टम एसआइटी की उपस्थिति में वेयरहाउस नंबर दो मुंद्रा पोर्ट पर छापा मार साइकोट्रोपिक पदार्थों की भारी बरामदगी। मोहम्मद आबिद, मदनपुर खादर का रहने वाला है। पहले जानवरों के चारे का बिजनेस था। बाद में साइकोट्रोपिक चीजों के गैर-कानूनी धंधे में शामिल हो गया जावेद खान, कस्टम्स हाउस एजेंट के तौर पर काम करता था, जो कंसाइनमेंट के डॉक्यूमेंटेशन और क्लियरेंस का काम करता था। लॉजिस्टिक्स और कस्टम्स प्रोसीजर की

अपनी जानकारी का फायदा उठाकर, उसने गैर-कानूनी फायदे के लिए प्रतिबंधित दवाओं की मूवमेंट में मदद की। सुनील कुमार, समालका में ÷प्रहलाद लाजिस्टिक्स÷ नाम से वेयरहाउस चलाता है। अपने वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस आपरेशन का इस्तेमाल करके, उसने संगठित नेटवर्क के हिस्से के तौर पर प्रतिबंधित सामान के स्टोरेज और आगे की मूवमेंट में मदद की। विष्णु दत्त शर्मा एमसीए है। वह आठ सालों से एक्सपोर्टर के तौर पर काम कर रहा था, जो मुख्य रूप से भारत से यूनाइटेड किंगडम में घरेलू सामान एक्सपोर्ट करता था। जांच के दौरान पता चला कि उसने अपने एक्सपोर्ट बिजनेस प्लेटफार्म का गलत इस्तेमाल करके सही कंसाइनमेंट की आड़ में साइकोट्रोपिक पदार्थों को छिपाने और भेजने का काम किया। विकास सिंह बीएससी ग्रेजुएट है और क्विक कार्गो कूरियर सर्विस के नाम से कोरियर कंपनी चलाता था। कोरियर और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का इस्तेमाल करके, उसने सप्लाई चेन के अंदर गैर-कानूनी दवाइयों के कंसाइनमेंट को कोआर्डिनेट करने और ट्रांसपोर्ट करने में मदद की।

मेरा बेडरूम खाली है, आजमा ले, पता चल जाएगा नॉर्थ-ईस्ट की लड़कियों से पड़ोसी महिला ने की बदसलूकी

नई दिल्ली। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक फ्लैट में एसी लगवाने के दौरान पड़ोसी के घर में धूल मिट्टी गिरने के बाद विवाद हो गया। आरोप है कि पड़ोसी ने उत्तर-पूर्व की रहने वाली तीन छात्राओं के साथ बदसलूकी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच-बचाव किया। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी शख्स व उसकी पत्नी ने मिलकर उनके खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करने के अलावा अभद्र भाषा का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी। करीब चार मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दोनों तरफ से काफी बहस हो रही है। वीडियो में आरोपी कपल की अभद्रता करते दिख रही है। पड़ोसी महिला नॉर्थ-ईस्ट की लड़कियों से कहती है कि मेरा बेडरूम खाली है, जा आजमा ले, पता चलेगा कितना बुड्ढा है। 35 साल का लड़का तेरे यहां बुड्ढा होता होगा। तेरी औकात नहीं है, जहां से वो आया है। कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो।

पॉलिटिशियन है उसका बाप। महिला आगे कहती है कि मेरे को मसाज पार्लर में मिला है क्या? मसाज पार्लर में धंधा करने बैठी थी क्या जो तूने देखा। जबान पर काबू रख अपनी। तेरे यहां आदमी मसाज पार्लर में काम करते हैं। मेरे यहां नहीं। जब यह विवाद हो रहा था, उस दौरान एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद था। हालांकि वो बीच-बचाव का प्रयास करता रहा। लेकिन आरोपी दंपती पुलिस के सामने बेखौफ टिप्पणी करते रहे। पड़ोसी महिला ने लड़कियों को गटर-छाप तक कहा। नस्लभेदी टिप्पणियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज

मालवीय नगर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्राओं की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 79, 351(2), 3(5), 196 (आईपीसी की धारा 509, 506, 153ए और 34) के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी पड़ोसी हर्ष सिंह एक पीआर कंपनी में काम करने के अलावा यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है। पुलिस वीडियो को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। दक्षिण जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना 20 फरवरी की है। मालवीय नगर की इमारत में उत्तर-पूर्वी राज्यों की रहने वाली तीनों युवतियां चौथी मंजिल पर पिछले सात माह से किराये के फ्लैट में रहती हैं। तीनों कॉलेज की छात्रा हैं।

20 फरवरी को हुआ पूरा मामला

इसी इमारत में तीसरी मंजिल पर हर्ष सिंह, उसकी पत्नी रूबी जैन व परिवार रहता है। पुलिस को दिए बयान में छात्राओं ने बताया कि 20 फरवरी दोपहर को वह अपने फ्लैट में एसी लगवा रही थीं। इस बीच काम की वजह से धूल नीचे रहने वाले हर्ष के फ्लैट में जाने लगी।

हर्ष ने इसका विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। युवतियों का आरोप है कि हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी ने उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। उनके खिलाफ जानबूझकर आपत्तिजनक व नस्लीय टिप्पणियां की गईं। पुलिस ने छात्राओं का बयान लेकर शनिवार को मामला दर्ज कर लिया।

रैपिड रेल के बाद सराय काले खां आईएसबीटी पर फोकस करेगी दिल्ली सरकार, यात्रियों को मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

नई दिल्ली। रैपिड रेल के शुरू हो जाने से सराय काले खां अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनलों (आईएसबीटी) पर दिल्ली सरकार फोकस करने जा रही है। सबसे पहले इसी आईएसबीटी के उन्नयन पर ध्यान दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार शहर के तीन अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनलों (आईएसबीटी) सराय काले खां, आनंद विहार और कश्मीरी गेट पर अगले माह से व्यापक उन्नयन (अपग्रेडेशन) शुरू करने जा रही है। जिसका लक्ष्य छह महीने में पूरा करना है। मगर अब सराय काले खां प्राथमिकता में आ गया है।

नवीनीकरण कार्य में खर्च होंगे 34 करोड़

दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआइडीसी) द्वारा शुरू किए जाने वाले इस नवीनीकरण कार्य की अनुमानित लागत 34 करोड़ है। इसमें नागरिक, विद्युत और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मरम्मत के साथ-साथ आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली की स्थापना, आरएफआइडी आधारित प्रवेश निगरानी और वाणिज्यिक और यात्री सुविधाओं का विस्तार शामिल होगा।

तीनों आईएसबीटी के पुनर्विकास पर अगले माह से शुरू होगा काम

योजना के तहत वास्तविक समय में बस के आगमन और प्रस्थान की जानकारी दिखाने वाले एलईडी डिस्प्ले बोर्ड और आरएफआईडी-आधारित बूम बैरियर परिचालन निगरानी में सुधार के लिए स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना में कुशल कामकाज सुनिश्चित करने के लिए विद्युत प्रणालियों, भवन अवसंरचना, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा प्रणालियों का रखरखाव और उन्नयन शामिल है।

यात्रियों की आवाजाही होगी और आसान

यह पहल दिल्ली सरकार के शहर के आईएसबीटी को हवाई अड्डे जैसी अवसंरचना और आधुनिक सुविधाओं वाले विश्व स्तरीय यात्री टर्मिनलों में पुनर्विकास करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। पुनर्विकास रोड मैप के हिस्से के रूप में यात्रियों के टर्मिनलों के भीतर आसान आवाजाही की सुविधा के लिए स्तर एस्केलेटर और ट्रैवलर (चलने वाले रास्ते) स्थापित किए जाएंगे, जिससे लंबी दूरी तक चलने की आवश्यकता कम हो जाएगी। इन उन्नयन का उद्देश्य व्यवस्थित बोर्डिंग और बेहतर यात्री प्रवाह सुनिश्चित करना है। इस योजना में स्वचालित टिकटिंग मशीनें, डिजिटल सूचना प्रणाली, बेहतर प्रतीक्षालय लाउंज और मनोरंजन क्षेत्र स्थापित करना भी शामिल है ताकि यात्रियों की सुविधा बढ़ाई जा सके।

एपस्टीन फाइल्स का कहर!

पिछले हफ्ते तक इंग्लैंड के युवराज रहे प्रिंस एंड्रयू की गिरफ्तारी ने एपस्टीन फाइल्स में उल्लेखित विश्व को मशहूर हस्तियों और राजनेताओं के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। यह एक ऐसा जिन्न है, जो फैलता ही जा रहा है। हर रोज नए-नए नाम और उनके काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि अमरीका के न्यायिक विभाग ने इन फाइल्स के सामने आने के बाद इनमें शामिल मशहूर हस्तियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही उनके खिलाफ कोई केस दर्ज किए क्योंकि उस पर अपने ही सत्ताधीशों का दबाव था। अमरीका के जो भी सांसद बारी-बारी से जाकर न्यायिक विभाग में इन फाइलों का निरीक्षण कर रहे हैं, वे सदमे में आ जाते हैं। इनमें दुनिया के कुलीन और मशहूर धनाढ्यों और राजनेताओं के नाम शामिल हैं। आश्चर्य की बात है कि भारत का अधिकतर मीडिया ही नहीं, बल्कि अमरीका का भी मुख्य धारा का मीडिया एपस्टीन फाइल्स को लेकर सामने आ रही दिल दहलाने वाली सूचनाओं को उस तत्परता से प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर रहा, जैसा किया जाना चाहिए। लगता है कि पैसे और ताकत के दबाव पर इन सूचनाओं को दबाने का काम जारी है। पर सोशल मीडिया अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। जिन्हें एपस्टीन फाइल्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे सोशल मीडिया पर जाकर क्षक्षक्षह्हद्दद्दद्ध ह्द्दद्दद्दह्ह कोवर्ड को खोजेंगे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये फाइल्स इतनी भयावह हैं कि अगर इनसे जुड़े ताकतवर लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी शुरू हो जाए तो अमरीका की राजसत्ता और आर्थिक सत्ता धराशायी हो जाएगी और यही स्थिति अन्य देशों में भी हो सकती है। आज अमरीका के हर बड़े शहर में लाखों नागरिक अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ सड़कों पर भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि इन संदिग्ध फाइल्स में उपलब्ध वीडियो फुटेज में डोनाल्ड ट्रम्प जैसी तमाम बड़ी हस्तियां, छोटी बच्चियों के साथ दिखाई दे रही हैं। हालांकि बच्चियों के यौन शोषण के मामले में उनके विरुद्ध अभी तक कोई प्रमाण सामने नहीं आए। आइए जान लें कि जैफरी एडवर्ड एपस्टीन कौन था? वह एक अमरीकी फाइनांसर (धन प्रबंधक) और सैक्स क्रिमिनल था। वह न्यूयॉर्क में जन्मा, पढ़ाई में अच्छा था, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर रहा, फिर वॉल स्ट्रीट पर 'बियर स्टर्न्स' जैसे बड़े बैंक में काम किया। बाद में उसने अपनी खुद की फर्म बनाई, जहां वह अरबपतियों के पैसे मैनेज करता था। वह बहुत अमीर हो गया और दुनिया के बड़े-बड़े लोगों से उसकी दोस्ती थी, जैसे पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रम्प, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयूज, बिल गेट्स, कई सैलिब्रिटी, वैज्ञानिक और बिजनैसमैन। उसके पास 'लोलिता एक्सप्रैस' नाम का प्राइवेट जेट था। न्यूयॉर्क व फ्लोरिडा में उसके महल जैसे घर और कैरिबियन में एक प्राइवेट द्वीप भी था, जहां वह शानदार दावतें देता था, जिनमें दुनिया भर की मशहूर हस्तियां शिरकत करती थीं। एपस्टीन पर बच्चियों और नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और सैक्स ट्रैफिकिंग (बलात्कार/दुष्कर्म का नैटवर्क चलाने) के गंभीर आरोप थे। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस ने जांच शुरू की तो एक 14 साल की लड़की ने बताया कि एपस्टीन ने उसे उसके घर में 'सैक्सुअल मसाज' के बहाने शोषण किया। दर्जनों (कुछ रिपोर्ट्स में 100 से ज्यादा) नाबालिग लड़कियों ने कहा कि एपस्टीन उन्हें पैसे देकर 'मसाज' के लिए बुलाता था, फिर सैक्सुअल एक्टिविटी करता था। उसकी पार्टनर घिस्लेन मैक्सवेल पर आरोप था कि वह एपस्टीन को लड़कियां मुहैया कराती थी। मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया और उसे 20 साल की सजा हुई और वह अभी जेल में है। उधर 2008 में एक डील हुई, जिसमें एपस्टीन ने अपना दोष स्वीकार किया और गिरफ्तार कर लिया गया। पर वह सिर्फ 13 महीने ही जेल में रहा। लेकिन 2019 में एपस्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर सैक्स ट्रैफिकिंग के फैडरल आरोप लगे। लेकिन फिर जेल में ही उसकी मौत हो गई। बताया गया कि उसने जेल में आत्महत्या कर ली। परंतु उसकी मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई। क्योंकि उस पर 24 घंटे निगरानी करने के लिए जेल में जो कैमरे लगे थे वे खराब हो गए थे, ऐसा बताया गया। इतना ही नहीं बताया गया कि उस पर चौकसी से हर वक्त निगाह रखने के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड भी सो गए थे। अमरीकी प्रशासन के ये स्पष्टीकरण एपस्टीन की मौत के कारणों को संदेहास्पद बना देते हैं। लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट सुसाइड की ही है। 2025-2026 में अमरीका में 'एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपैरेंसी एक्ट' पास हुआ। जिसके बाद अमरीका के न्यायिक विभाग ने लाखों पेज के डॉक्यूमैंट्स, फोटो, वीडियो रिलीज किए, जिनकी संख्या करीब 35 लाख पेज है। इनमें वे लाखों ईमेल भी हैं जिनका एपस्टीन और दुनिया के तमाम ताकतवर लोगों के साथ संवाद दर्ज है। कुछ ईमेल तो अनैतिकता की हदें पार करने वाली हैं। इसके अलावा तमाम अबोध बच्चियों के साथ हुए शारीरिक और मानसिक शोषण को दर्शाने वाली तमाम वीडियो और फोटो भी हैं। इससे पता चलता है कि एपस्टीन अपने हर मेहमान की हर गतिविधि का रिकॉर्ड सम्भाल कर रखता था। ऐसा प्राय: वही लोग करते हैं जो बाद में अपने इन महत्वपूर्ण संपर्कों को ब्लैकमेल करके उनसे बड़े-बड़े लाभ ले सकें। एपस्टीन की मौत के बावजूद भी अब यह केस सारी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है एपस्टीन के सैक्स कांड की पीड़िताओं ने संगठित हो कर यह संकल्प लिया है कि अब वे चुप नहीं रहेंगी और हर उस हस्ती का नाम उजागर करेंगी, जिसने उनकी कच्ची उम्र की परवाह न करते हुए उनका शारीरिक शोषण किया था। मीर तकी मीर का एक शे'र है, 'इब्तिदा-ए-इश्क है रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या।'

वोटर लिस्ट के बाद जज मुकद्दमों का समय पर निपटारा करें

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के विवादित वीडियो पर सुनवाई से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनावों से पहले नेताओं को अदालत में सियासी मुद्दे नहीं उठाने चाहिए लेकिन वोटर लिस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से हाईकोर्ट और जिला अदालतें भी नेताओं की सियासत में फंसती नजर आ रही हैं। राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच आरोप-प्रत्यारोप के दुर्भाग्यपूर्ण खेल की वजह से बढ़ रहे संवैधानिक संकट की ओर इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करने का आदेश पारित किया है। उसके अनुसार, हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की छुट्टी निरस्त करने के साथ वोटर लिस्ट से जुड़े विवादों के निपटारों के लिए 294 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट के 9 फरवरी के आदेश के अनुपालन की बजाय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस के वीडियो और होर्डिंग से सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश में जुटी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता से जुड़े आवेदनों की जांच और मंजूरी के लिए एक विशेष अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यह समिति नागरिकता अधिनियम 1955 और संशोधित नागरिकता कानून (सी.ए.ए.) के तहत नागरिकता का निर्धारण करेगी। सी.ए.ए. का कानून 2019 में बनाया गया, जिसके 5 साल बाद नियम बनाए गए। दिलचस्प बात यह है कि सी.ए.ए. कानून को चुनौती देने वाली 200 से ज्यादा लंबित पुरानी याचिकाओं पर चुनावी समर के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के बाद अब 5 साल के भीतर देश से सभी घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। लेकिन बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद कितने घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से निकाले गए, इसका अधिकृत आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया। विपक्षी दलों की यह आशंका कि एस.आई.आर. की प्रक्रिया से दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके भी ठोस प्रमाण सामने नहीं आ रहे। पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर ए.आई. के इस्तेमाल से मतदाता फोटो पहचान पत्र से लेकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले सामने आ रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि आधार कार्ड से लेकर सभी दस्तावेजों को फर्जी तरीके से बनाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद वोटर लिस्ट से जुड़े विवाद में तकनीक और ए.आई. का व्यावहारिक इस्तेमाल नहीं होना, दुखद होने के साथ पूरे देश में प्रशासनिक अराजकता को बढ़ा रहा है।

मृत या डुप्लीकेट वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार वोटर लिस्ट बनाने और चुनाव करवाने के बारे में चुनाव आयोग को सभी अधिकार हासिल हैं। कोई भी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संवैधानिक व्यवस्था का पालन करने में विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के अनेक आदेशों का पालन करने में विफल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित करने की बजाय न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से अन्य राज्यों में भी ऐसी मांग उठ सकती है। चुनाव आयोग ने असम में विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) की बजाय सामान्य पुनरीक्षण का निर्णय लिया है। असम में भी अन्य राज्यों की तर्ज पर एस.आई.आर. की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मतदाता सूची में पुनरीक्षण पर अधिकांश विवाद विपक्ष शासित राज्यों में ही हो रहा है लेकिन राजनीति के इस गंदे खेल में अदालतों और जजों की बढ़ती भूमिका से आने वाले समय में कई चुनौतियां आ सकती हैं। बंगाल में 45 लाख से ज्यादा मामलों में न्यायिक अधिकारी जो आदेश पारित करेंगे, उनके खिलाफ अब सिर्फ हाईकोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है। तीसरे चरण में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत 22 राज्यों में एस.आई.आर. की प्रक्रिया शुरू करने और वोटरों की मैपिंग के लिए चुनाव आयोग ने पत्र लिखा है। मिड डे मील, जनगणना, वोटर लिस्ट और चुनावों में शिक्षकों की ड्यूटी से शिक्षा प्रभावित हो रही है। अब वोटर लिस्ट से जुड़े विवादों के समाधान के लिए मैजिस्ट्रेट और जजों की नियुक्ति से अदालतों में लंबित मुकद्दमों का मर्ज बढ़ सकता है। अन्य राज्यों में भी वोटर लिस्ट से जुड़े विवाद भी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे। इसलिए इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट की बजाय राज्यों के हाईकोर्ट में सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार फैसला चाहिए।

पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर 45 लाख से ज्यादा मामलों का निष्पादन करना होगा। यदि यह काम समय पर सफलतापूर्वक पूरा हो जाए तो उसके बाद सभी जिला अदालतों के जजों को मुकद्दमों के समयबद्ध निष्पादन के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करना चाहिए।-विराग गुप्ता(एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट)

सम्पादकीय...

हुनर सीखने का अवसर

दिल्ली के भारत मंडपम में पहला 'इंडिया ए.आई. इम्पैक्ट समिट' आयोजित करने का भारत का फैसला केवल तकनीकी या कूटनीतिक नहीं, बल्कि यह एक गहरे बदलाव का संकेत है। यह बदलाव इस बात से जुड़ा है कि आने वाले समय में काम कैसे होगा। नौकरियां कैसे मिलेंगी? लोग अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आज आम धारणा यह बन रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ए.आई. लोगों की नौकरियां छीन लेगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। ए.आई. काम को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि पुराने और नष्ट हो चुके रोजगार के तरीकों को बदल रहा है और लोगों को नए हुनर सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है। ए.आई. खासतौर पर उन कामों को बहुत तेजी से और सटीक तरीके से कर सकता है, जो बार-बार दोहराए जाते हैं और जिनमें ज्यादा रचनात्मक सोच की जरूरत नहीं होती। जैसे रिपोर्ट बनाना, डाटा का विश्लेषण करना, सामान्य कोड लिखना, ग्राहक सेवा के सवालों के जवाब देना या दस्तावेजों को व्यवस्थित करना। पहले इन कामों के लिए बड़ी संख्या में जूनियर कर्मचारियों की जरूरत होती थी। अब वही काम ए.आई. कुछ ही मिनटों में कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि काम खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब यह है कि काम की प्रकृति तेजी से बदल रही है। इतिहास गवाह है कि हर नई तकनीक ने पुराने कामों को बदला है लेकिन साथ ही नए अवसर भी पैदा किए हैं। जब मशीनें आईं, तो हाथ से काम करने वाले कारीगरों की जरूरत कम हुई, लेकिन इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर और मैनेजर जैसे नए पेशे सामने आए। 1990 के दशक में कम्प्यूटर आए, तो टाइपिस्ट और क्लर्क की जरूरत कम नहीं हुई, बल्कि वे भी कम्प्यूटर सीख कर काम में तेजी लाए। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ और डाटा विश्लेषक जैसे नए पेशे पैदा हुए। आज ए.आई. उसी प्रक्रिया का अगला चरण है। ए.आई. की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इंसानों की जगह लेने की बजाय उनकी क्षमता को बढ़ाता है। ए.आई. जानकारी दे सकता है, सुझाव दे सकता है और कई कामों को आसान बना सकता है लेकिन अंतिम निर्णय लेना, सही दिशा तय करना और जटिल समस्याओं को समझना अभी भी इंसानों की जिम्मेदारी है। उदाहरण के लिए, ए.आई. कोड लिख सकता है लेकिन यह तय करना कि उस कोड का इस्तेमाल कैसे होगा और वह किसी कंपनी या समाज के लिए कितना उपयोगी होगा, यह इंसान ही तय करता है। इसी तरह, ए.आई. डॉक्टर की मदद कर सकता है लेकिन मरीज के साथ बातचीत करना और उसकी बीमारी व भावनाओं को डॉक्टर ही समझ सकता है। इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि अब केवल डिग्रीधारी होना काफी नहीं होगा। अब सबसे जरूरी है लगातार नए हुनर सीखना। इसमें सोचने की क्षमता, समस्या सुलझाने की योग्यता, रचनात्मकता और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढलने की क्षमता विकसित करने की जरूरत है। भारत के लिए यह बदलाव एक बड़ी चुनौती होने के साथ एक बड़ा अवसर भी है। भारत की युवा आबादी, मजबूत डिजिटल ढांचा और तेजी से बढ़ती तकनीकी क्षमता इसे ए.आई. युग में अग्रणी बना सकती है।

जाति संघर्ष का सर्वसमावेशी समाधान वक्त की जरूरत

मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद से जिस तरह का राजनीतिक विमर्श स्थापित हुआ, उसमें सवर्ण समाज अपने लोगों के विकास और आरक्षण विरोध की बात करने की हिम्मत नहीं दिखा पाता था। ऐसा करने से उसे दकियानूस माने जाने का खतरा नजर आता था। इसलिए उसने चुप्पी साधे रखी। लेकिन बाद के वर्षों में एससी-एसटी कानून का सवर्ण समाज के खिलाफ जारी दुरूपयोग ने सामाजिक रूप से आगे माने जाते रहे वर्णों और जातियों को मौका मिला। बाढ़ का पानी जब नाक तक पहुंच जाता था, तब व्यक्ति उससे बचाव के लिए छटपटाने लगता है। सवर्ण समाज के लिए यूजीसी की गाइडलाइन नाक तक पहुंचा बाढ़ का पानी है। उसी पानी से बचाव की छटपटाहट ही है कि गाइडलाइन के खिलाफ समूचे देश के सवर्ण समाज में गहन क्षोभ और गुस्सा नजर आ रहा है। अब सवर्ण समुदाय के नौजवान तर्क देने से हिचक नहीं रहे कि जब पिछड़ावाद हो सकता है, दलितवाद प्रगतिशील विचार हो सकता है, अल्पसंख्यकवाद सामाजिक न्याय का प्रतीक हो सकता है तो ब्राह्मणवाद या सवर्णवाद दकियानूस क्यों?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के दिशा-निर्देशों से ना सिर्फ जाति विमर्श केंद्र में आ गया है, बल्कि हिंदू समाज जातीय खांचे में बंटता नजर आ रहा है। आर्थिक और शैक्षिक विकास की वजह से जाति विभाजन की जो रेखाएं मध्यम पड़ने लगी थीं, वे एक बार फिर गहरी होती नजर आ रही हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद जैसा स्पष्ट विभाजन हिंदू समाज में दिख रहा था, कुछ उसी राह पर एक बार फिर समाज बढ़ता दिख रहा है। जाति के तवे पर राजनीतिक रोटी सेंकने वाले कुछ दल यूजीसी की गाइडलाइन को लागू करने के लिए छात्रों के बीच जाति विमर्श की आंच को हवा दे रहे हैं तो इस गाइडलाइन के विरोध में खड़े सवर्ण समाज के लोग भी अपने समाज के छात्रों को लामबंद करने में प्राणपण से जुटे हुए हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह नया राजनीतिक विमर्श खड़ा हुआ, जिससे कुछ राजनीतिक दलों और शख्सियतों को उभरने का मौका मिला, कुछ वैसे ही हालात एक बार फिर बनते दिख रहे हैं। अगर यूजीसी गाइडलाइन का सर्वसमावेशी हल नहीं खोजा गया तो हिंदुत्व की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। हिंदू एकता का सपना भी खतरे में पड़ सकता है। राजनीति के बारे में एक धारणा है। सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास ने जाति विभाजन को जहां कमजोर किया, वहीं राजनीति इसे जिंदा करने में सफल हुई है। सामाजिक यात्रा में पिछड़ी रह गई जातियों के उत्थान के नाम पर राजनीति ने जाति विमर्श को केंद्र में लाने का सबसे बड़ा योगदान विश्वनाथ प्रताप सिंह को जाता है, जिन्होंने देवीलाल के राजनीतिक रसूख को काबू में करने के लिए 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट पर पड़ी धूल को झाड़ा और उसे लागू कर दिया। पैंतीस साल पहले के उस फैसले ने समाज को बुरी तरह विभाजित कर दिया। मंडल आयोग के खिलाफ तकरीबन समूचा उत्तर भारत धधक उठा था। सवर्ण समुदाय के छात्रों और नौजवानों को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा था। उन्होंने खुद को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह कविता भी करते थे। कवि को लेकर धारणा है है कि वह कोमल हृदय का स्वामी होता है। लेकिन आग की लपटों के बीच धू-धूकर जवानी को जलती देखकर भी कवि हृदय प्रधान मंत्री नहीं पसीजे थे। उस दौर के शरद यादव सवर्ण समाज के कटु आलोचक और पिछड़ावादी राजनीति के प्रबल पैरोकार के रूप में उभरे। मंडल आयोग की रिपोर्ट से समाज के बीच जो खाई पैदा हुई, बाद की राजनीति ने उसे और ज्यादा चौड़ा और गहरा ही किया है। पिछड़ों को आरक्षण को समाज ने स्वीकार कर लिया था, तभी दूसरे सवर्ण और मनमोहन सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने साल 2006 में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण की शुरूआत कर दी। इसके विरोध में एक बार फिर युवा राजनीति उभरी। यूथ फॉर इक्वलिटी के बैनर तले दिल्ली में इस फैसले के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर पड़े। इस आंदोलन के चलते भी सामाजिक विभाजन बढ़ा। शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण के विरोधी समुदायों और इसके समर्थक समुदायों के बीच एक बार फिर विभाजक रेखा गहरी हुई। इससे भी देश उबर रहा था कि यूजीसी की गाइडलाइन आ गई और फिर से एक बार भारतीय समाज गहरे अंतर्द्वंद्व और सामाजिक संघर्ष से जूझने लगा। यह संघर्ष अभी समाज में सीधे तो नहीं दिख रहा, लेकिन विश्वविद्यालयों के परिसर इसके चलते उबल रहे हैं। एक तरफ इस गाइडलाइन के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ उसके विरोधी। आज पिछड़ावाद, दलितवाद, अल्पसंख्यकवाद और महिलावाद का जोर है। इन तबकों के उभार के विचार को सामाजिक न्याय करीब साढ़े तीन दशकों से स्वीकार किया जा रहा है। इन वादों को सामाजिक लोकवृत्त यानी पब्लिक स्फीयर के केंद्र में लाने का विचार समाजवादी राजनीतिक दलों का रहा है, लेकिन इसे मूर्त रूप में लाने वाले कांग्रेसी मूल के राजनेता ही रहे हैं। समाजवादी दलों के ही परोक्ष समर्थन से पहली बार तीस मई 1933 को बिहार के मौजूदा रोहतास जिले के करगहर में त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई थी। जिसमें कोइरी यानी कुशवाहा, कुर्मी और यादव जातियों के नेता साथ आए थे और पिछड़ावादी राजनीति की नींव डाली थी। एक तरह से जातिवादी राजनीति की नींव आजादी के पहले ही पड़ गई थी। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह भले ही जनता दल नामक समाजवादी विचारधारा वाले दल के नेता थे, लेकिन महज तीन साल पहले तक वे कांग्रेसी थे। अर्जुन सिंह भी कांग्रेसी ही थे। आज राहुल गांधी भी जाति जनगणना को लेकर उत्साहित नजर आते हैं। पता नहीं राहुल गांधी को पता है या नहीं, अर्जुन सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह को जानकारी जरूर रही होगी। राहुल गांधी को दादी के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 27 जून 1961 को देश के मुख्यमंत्रियों के नाम तीस पैराग्राफ का एक लंबा खत लिखा था। उसके चौबीसवें से छब्बीसवें पैरे में नेहरू ने आज की जाति आधारित आरक्षण को एक तरह से नकार दिया है। उस चिट्ठी में उन्होंने भारत को बनाने को लेकर उनकी जो सोच रही, उसका गहन जिक्र किया है। इस पत्र में नेहरू स्पष्ट रूप से अपने विचार को जाहिर करते हैं। वे आरक्षण आधारित विकास और समान नहीं चाहते थे, बल्कि ज्ञान केंद्रित समाज का विकास चाहते थे। नेहरू के लिखा था, मुझे किसी भी रूप में आरक्षण पसंद नहीं है। खासकर नौकरियों में आरक्षण। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अक्षमता को बढ़ावा देता है और हमें औसत दर्जे की ओर ले जाता है। यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध कर रहे लोग अगर आज यही बात कहें तो उन्हें सामाजिक न्याय का विरोधी माना जाएगा। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद से जिस तरह का राजनीतिक विमर्श स्थापित हुआ, उसमें सवर्ण समाज अपने लोगों के विकास और आरक्षण विरोध की बात करने की हिम्मत नहीं दिखा पाता था। ऐसा करने से उसे दकियानूस माने जाने का खतरा नजर आता था। इसलिए उसने चुप्पी साधे रखी। लेकिन बाद के वर्षों में एससी-एसटी कानून का सवर्ण समाज के खिलाफ जारी दुरूपयोग ने सामाजिक रूप से आगे माने जाते रहे वर्णों और जातियों को मौका मिला। बाढ़ का पानी जब नाक तक पहुंच जाता था, तब व्यक्ति उससे बचाव के लिए छटपटाने लगता है। सवर्ण समाज के लिए यूजीसी की गाइडलाइन नाक तक पहुंचा बाढ़ का पानी है। उसी पानी से बचाव की छटपटाहट ही है कि गाइडलाइन के खिलाफ समूचे देश के सवर्ण समाज में गहन क्षोभ और गुस्सा नजर आ रहा है। अब सवर्ण समुदाय के नौजवान तर्क देने से हिचक नहीं रहे कि जब पिछड़ावाद हो सकता है, दलितवाद प्रगतिशील विचार हो सकता है, अल्पसंख्यकवाद सामाजिक न्याय का प्रतीक हो सकता है तो ब्राह्मणवाद या सवर्णवाद दकियानूस क्यों? सवर्ण समुदाय के बच्चों का कहना है कि माना कि उनके पूर्वजों ने गलती की तो उसकी सजा हम क्यों भुगतें। ध्यान देने की बात है कि राममंदिर आंदोलन के बाद सवर्ण समाज ने पूरी तरह बीजेपी का दामन थाम लिया। उसे बीजेपी में अपनी दबी भावनाओं की अभिव्यक्ति की राह दिखती रही है। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन से वह भौंचक्क रह गया। यही भौंचक्कापन अब गुस्से के रूप में नजर आ रहा है। सत्ता पर निगाह जमाए बैठे विपक्षी दल पर्दे के पीछे से इस गुस्से को हवा दे रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें पिछड़ा वोटर के बिदकने का खतरा भी नजर आ रहा है, इसी सोच के चलते वे गाइडलाइन के खिलाफ खुलकर कुछ बोलने से बच रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी में इस आफत की काट नहीं खोजी जा रही होगी। बीजेपी संगठन और सरकार के आलानेता इस जातीय विमर्श को ठंडा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान ढूंढने में जितनी देर होगी, जाति विमर्श उतना ही बढ़ेगा। अगर सवर्ण समुदाय का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बीजेपी की चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

एआई की बुद्धिमत्ता और हमारी मूर्खताएं

भगवती चरण वर्मा की कहानी है 'वसीयत'। उसमें पंडित चूड़ामणि मिश्र के परिवार के लोग जीते जी उनकी उपेक्षा करते हैं लेकिन उनकी मृत्यु के उपरांत धन के लालच में वसीयत पढ़े जाते समय प्रेम और सम्मान का दिखावा करते हैं। जिस उत्तराधिकारी की आलोचना होती है वह कुढ़ता है और जब कुछ मिल जाता है तो वह प्रशंसा करने लगता है। बाद में वसीयत में पंडित तोते के स्वर में अपने शिष्य जनार्दन जोशी से कहते हैं तुम मूर्ख हो और मैं पंडित। कहीं ऐसा न हो कि होमो सेपियन्स की मानव प्रजाति अपने निधन के बाद जो वसीयत छोड़ जाए उसको लेकर उसकी संतानें कुछ वैसा ही नाटक करें और जो नैतिकता की बात करे उसे बुद्धू बता दिया जाए। इजराइल के मशहूर इतिहासकार युआल नोवा हरारी अपनी पुस्तक नेक्सस में कहते हैं कि हमारी प्रजाति बहुत बुद्धिमान है। क्योंकि उसने बेहतहाशा तरक्की की है। लेकिन वह मूर्ख भी है क्योंकि वह अपने विनाश के उपकरण लगातार जमा करती जा रही है। वे कहते हैं कि जर्मनी ने एक अधिनायकवादी उपकरण खड़ा किया और तकरीबन एक करोड़ लोगों की जान ली। आखिर में वह खुद भी धराशायी हो गया। लेकिन अब विनाश के उपकरण सार्वभौमिक हो गए हैं। वे मानव के नियंत्रण से बाहर निकलने को छटपटा रहे हैं। सर्वसत्तावाद सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में पैदा हुई लोकतंत्र की लहर को शांत करता हुआ झूठ, अनैतिकता, सत्तालोलुपता, अफवाह, दुर्भावनापूर्ण सूचनाएं, युद्ध और विनाश के नए औजारों को बांटते हुए नई सृष्टि का सृजन कर रहा है। इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संपन्न सभ्यता नए किस्म की मूर्खताओं की ओर अग्रसर हो रही है। जो लोग दूसरों को मूर्ख और स्वयं को अधिक बुद्धिमान समझते हैं वे कितने किस्म की मूर्खताएं करते हैं उसकी तमाम कहानियां हमारी लोककथाओं में बिखरी पड़ी हैं। जैसे तीन जगह गंदगी लगने वाली कहानियां। उसकी एक झलक हाल में दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में दिखाई पड़ी। जो सम्मेलन एआई से जुड़े मानव प्रजाति के गंभीर सवालों पर चर्चा के लिए आयोजित हुआ था और जिस पर भारतीय मीडिया में तमाम पन्ने और घंटे खर्च भी किए वह कुल मिलाकर कुछ नेताओं के अहंकार और कुछ संस्थाओं के झूठ और मूर्खताओं का आयोजन बनकर रह गया। संभव है कुछ अच्छी बातें हुई हों और कुछ सवाल उठे हों लेकिन बाहर जो संदेश गया वो यही गया कि गलगोटिया विश्वविद्यालय ने ओरियो(एक कुत्ता) नाम के एक रोबो को अपने केंद्र में विकसित बताकर दर्शाया और उसे आईटी मंत्री ने अपने ट्विट पर प्रचारित किया लेकिन बाद में जब चीन और नेटीजन ने यह असलियत उजागर की कि वह तो उसकी यूनीट्री नाम की कंपनी ने जीओ 2 नाम से विकसित किया है तो उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। यानी संसार को मूर्ख बनाने चले खुद ही मूर्ख बन गए। फिर तो एपस्टीन फाइल्स में विवादित माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के भाषण का न होना और बाद में ओपेन एआई सीईओ सैम आल्टमैन का यह कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ कर उठा दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसी तरह की एक घटना उस समय भी हुई जब ओपेन एआई के सीईओ आल्टमैन और एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई का हाथ मिलवाने की कोशिश हुई और वे दोनों अपनी मुट्ठी ही बांधे रहे। उन्होंने ऊपर उठा हुआ हाथ एक दूसरे से नहीं मिलाया। वे दोनों कंपनियां एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी हैं। पंडित चूड़ामणि मिश्र की संतानों की इस लोभ लालच, पाखंड और फरेब देखकर संदेह होता है कि वे वास्तव में पंडित जी की विरासत के साथ क्या करेंगे। एआई पर होने वाला यह पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नहीं था और न ही भारत ने इसमें कोई विशेष किस्म का नवोन्मेष किया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अपने 'मानव' संबंधी जुमले के माध्यम से उन नैतिक सवालों को उठाने की एक हद तक कोशिश की जो पहले उठते रहे हैं। जैसा कि हमारी सरकार हर चीज का लोकलुभावन संक्षेपीकरण करती है वैसा इस 'मानव' के मामले में भी था। यहां एम का अर्थ मॉरल से था, ए से अकाउंटेबिलिटी, एन से नेशनल सावरेनिटी, ए से एक्सेसबल/इनक्लूसिव और वी से वैलिड/ लेजिटिमेट का मतलब था। यानी यह सम्मेलन नैतिकता, राष्ट्रीय संप्रभुता, पहुंच, समावेशिता, वैधता पर केंद्रित था। इस बारे में पहला सम्मेलन ग्रेट ब्रिटेन के ब्लेटचेली पार्क में 2023 में हुआ था। उसका जोर इस बात पर था कि एआई से पैदा होने वाले खतरे को संभालने के लिए कैसे वैश्विक सहयोग विकसित किया जाए। उसके बाद दूसरा सम्मेलन दक्षिण कोरिया के सिओल में 2024 में हुआ। उस सम्मेलन में 27 देश इस बात पर राजी हुए कि किस प्रकार एआई से सुरक्षित रहने के लिए एक नेटवर्क बनाया जाए जो कि मानक निर्धारित करे। तीसरा सम्मेलन पेरिस में 2025 में हुआ जहां पर यह तय किया गया कि किस प्रकार इसके एकाधिकार को रोकने के लिए पारदर्शी एआई आधारभूत ढांचा बनाया जाए। एआई के बारे में जो गंभीर सवाल है क्या वे हमारी चिंताओं में है या फिर हम अपने को तकनीकी महाशक्ति दर्शाने या महाशक्तियों के साथ खड़े होने की होड़ में उनकी उपेक्षा करते जा रहे हैं? एआई के तमाम विशेषज्ञों ने जो सवाल और संदेह खड़े किए हैं उन पर हमें विचार करना ही चाहिए और उनके समाधान की दिशा में बढ़ना चाहिए। सबसे पहले ज्योफ्री हिल्टन जिन्हें एआई का जनक कहा जाता है उनकी चिंताओं को देखना चाहिए। हिल्टन ने साफ तौर पर अफसोस जताया है कि काश! मैंने यह आविष्कार न किया होता। यह मानवता के लिए खतरा है। क्योंकि एआई अगले 20 वर्षों में मानव जाति की बुद्धिमत्ता को पीछे छोड़ सकती है। यह शैतानी शक्तियों के हाथों में पड़ सकती है और इससे जैविक हथियार बनाए जाने, बड़े पैमाने पर विस्थापन, बेरोजगारी, सामाजिक अस्थिरता और मानव के नियंत्रण के बाहर होने का खतरा है। इसी तरह की चिंता एक और विशेषज्ञ योशुआ बेंजियो ने भी जताई है।

उनका कहना है कि इससे विनाशकारी खतरा है। एआई से जुड़े नैतिक सवाल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी उठते रहे हैं। जैसे कि बेरोजगारी, असमानता, मानवता, कृत्रिम मूर्खता, नस्ली रोबो, सुरक्षा, शैतानी शक्तियां, अनियंत्रण की चुनौती और रोबो के अधिकार। अभी एआई के बारे में जो समझाइश दी जा रही है वो यही है कि पहले भी जब नई मशीनें आई थीं तो इसी तरह के तर्क दिए जाते थे कि उनसे मानव का रोजगार छिन जाएगा। लेकिन सभ्यता चली जा रही है और कोई खास दिक्कत नहीं आई। जब एआई मनुष्य ने बनाया है तो वह उसे नियंत्रित करना भी चाहेगा और अगर चाहेगा तो वह नियंत्रित कर लेगा। जो लोग बेरोजगार होंगे वे मानव समाज की सेवा के काम में लगेंगे। एक तरह से मनुष्य के पास रचनात्मक अवकाश होगा। क्योंकि दफ्तरों, शिक्षण संस्थाओं, फैक्टरियों, सेनाओं के काम को तो एआई संभालने जा रहा है। अगर एआई के माध्यम से ट्रक और गाड़ियां चलाने पर कम दुर्घटनाएं होती हैं तो एआई क्यों बुरा है। इससे तो मानवता सुरक्षित होगी। लेकिन एआई से पैदा होने वाले खतरों को हम दुनिया में बढ़ते युद्ध और नवसाम्राज्यवाद के खतरों से अलग करके नहीं देख सकते। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 20 जनवरी 2026 को वर्ल्ड इकानामिक फोरम की दावोस बैठक में जो बात कही है उस पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना था कि पुरानी विश्व व्यवस्था भीतर से फट गई है। नई विश्व व्यवस्था बननी चाहिए लेकिन वह अभी बन नहीं पाई है। दूसरी ओर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने म्यूनिख के सुरक्षा सम्मेलन में फरवरी में दिए अपने भाषण में कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विऔपनिवेशीकरण का दौर चला वह वास्तव में पतन का दौर था। इसलिए अगर हमें पश्चिम की नई सदी कायम करनी है तो विश्व युद्ध से पूर्व के औपनिवेशिक दौर की प्रासंगिकता के बारे में सोचना चाहिए। एआई के बढ़ते प्रभाव और हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली स्वचालित नाभिकीय मिसाइलों के आविष्कार की रोशनी में इन इरादों को देखना चाहिए। कुछ विश्लेषक इसे डाटा साम्राज्यवाद के रूप में भी देखते हैं और कुछ एकाधिकारवाद के रूप में भी देखते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/[illegible])

फ्यूचर स्किल प्राइम सरीखी पहल वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तैयारी में महत्वपूर्णः वीसी

टीएमयू में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के तत्वावधान में फ्यूचर स्किल प्राइम पर ओरिएंटेशन सत्र

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के कुलपति प्रो. वीके जैन ने कहा, यह कौशल-आधारित शिक्षा का युग है। उन्होंने स्टुडेंट्स से कहा कि तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ उद्योग की मांग के अनुरूप कौशल विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए फ्यूचर स्किल प्राइम सरीखी पहल स्टुडेंट्स को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने निरंतर सीखने की मानसिकता अपनाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए स्वयं को अपडेट रखने की प्रेरणा दी। प्रो. जैन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के तत्वावधान में नासकॉम के सहयोग से फ्यूचर स्किल प्राइम पर आयोजित ओरिएंटेशन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इससे पूर्व कुलपति प्रो. वीके जैन, सीटीएलडी के निदेशक प्रो. पंकज कुमार सिंह, नासकॉम के कस्टमर सक्सेस ऑकित सिन्हा, इंस्टेलिंग डॉट एआई के फाउंडर एवम् सीईओ जुबैर चौधरी आदि ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्र'ज्वलित करके सीसीएसआईटी के लेक्चर थिएटर-6 में ओरिएंटेशन सत्र का शुभारम्भ किया। सभी अतिथियों को बुके देकर स्वागत और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। रिसोर्स पर्सन नासकॉम के कस्टमर सक्सेस श्री ऑकित सिन्हा ने फ्यूचर स्किल प्राइम प्लेटफॉर्म की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा,

यह पहल स्टुडेंट्स को उद्योग के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, प्रमाणन और रोजगार अवसर प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थान एक साझा मंच पर आकर कौशल विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने स्टुडेंट्स को डिजिटल लर्निंग के महत्व, स्व-प्रेरित अध्ययन और उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण के लाभों के बारे में विस्तार से समझाया। इंस्टेलिंग डॉट एआई के फाउंडर एवम् सीईओ जुबैर चौधरी ने स्टुडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई आधारित भर्ती प्रक्रियाओं और डिजिटल जॉब मार्केट के बदलते स्वरूप से अवगत कराया। उन्होंने बताया, वर्तमान समय में कंपनियां डेटा आधारित निर्णय लेने पर अधिक ध्यान दे रही हैं। उन्होंने स्टुडेंट्स को सलाह दी कि वे तकनीकी कौशल के साथ अपनी विश्लेषणात्मक सोच, संचार क्षमता और समस्या समाधान कौशल को मजबूत बनाएं। उन्होंने अपने स्टार्टअप अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों को उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सीटीएलडी के निदेशक प्रो. पंकज कुमार सिंह ने कहा, टीएमयू सदैव स्टुडेंट्स को उद्योगोन्मुख शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्यूचर स्किल प्राइम प्लेटफॉर्म स्टुडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और अन्य उभरती तकनीकों में प्रशिक्षित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने छात्रों से ऐसे प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग करने और अपने करियर विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किय प्रश्नोत्तर सत्र में स्टुडेंट्स ने फ्यूचर स्किल प्राइम प्लेटफॉर्म पर प्रमाणन प्राप्त करने, रोजगार के अवसर बढ़ने, एआई और डेटा साइंस में करियर बनाने के लिए आवश्यक कौशलों की आवश्यकता, उद्योग में चयन प्रक्रिया में सहायक व्यवहारिक गुणों को लेकर प्रश्न पूछे। संसाधन व्यक्तियों ने सभी प्रश्नों के व्यावहारिक और विस्तृत उत्तर दिए। सीटीएलडी के डॉ. दिलीप दत्त वर्ष्णेय ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

जयंती पर याद किये गये बाबा संत गाडगे

मुरादाबाद।

महान समाज सुधारक एवं संत परंपरा के अग्रदूत बाबा संत गाडगे महाराज की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ द्वारा डॉ आंबेडकर पार्क सिविल लाइन में बाबा संत गाडगे महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके द्वारा किए गए महान कार्यों पर संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य ने विस्तार से प्रकाश डाला। बताया कि संत गाडगे महाराज का जन्म 23 फरवरी 1876 में महाराष्ट्र प्रांत के अमरावती जिले के गांव शेणपुर में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा, स्वच्छता अभियान, अंधविश्वास उन्मूलन और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में समर्पित कर दिया और उन्होंने गांव-गांव घूमकर अंधविश्वास में दुबे लोगों को जगाया और 31 शिक्षण संस्थाएं खोलकर जिसमें एक उच्चतर विद्यालय और एक महाविद्यालय भी शामिल है जैसे महान कार्य करते हुए संत गाडगे की उपाधि प्राप्त की। बाबा संत गाडगे को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपना गुरु माना है संत गाडगे द्वारा किए गए महान कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता आगे अम्बेडकर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेन्द्रपाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि संत गाडगे महाराज का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि आज समाज में स्वच्छता, समानता और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी जागरूकता दिखाई देती है, उसमें संत गाडगे महाराज जैसे महापुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज में भाईचारा और समरसता स्थापित करनी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. एच. एन. प्रसाद ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संत गाडगे महाराज ने दलित, वंचित और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगो ने संत गाडगे महाराज के आदर्शों पर चलने और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संघ के कोषाध्यक्ष मलखान सिंह, जय प्रकाश सिंह परजीत सिंह सुनील कुमार आदि उपस्थित रहे।

चकबंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत गांवों में लगेंगी चौपालें

मुरादाबाद।

बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी राजेन्द्र राम ने बताया कि जनपद के ग्रामों में समुचित प्रचार-प्रसार के उपरान्त तिथि व स्थान निर्धारित करते हुए समय सारणी बनाकर ग्राम चौपाल का आयोजन सुनिश्चित करते हुए कृषकों का फीडबैक प्राप्त कर उनकी समस्याओं का निराकरण किए जाने तथा इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को ग्राम चटकाली में अपरान्ह 3:00 बजे एवं 27 फरवरी को अपरान्ह 3 बजे ग्राम बढेरा में उप संचालक चकबंदी की उपस्थित में ग्राम चौपाल आयोजित होगी। ग्राम रफातपुरा में 26 फरवरी को अपरान्ह 3 बजे से बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी की उपस्थित में चौपाल का आयोजन होगा। इसके साथ ही 25 फरवरी को ग्राम रनियाठेर में प्रातः 11 बजे से तथा ग्राम रहटामाफी ऐहतमाली में 26 फरवरी को प्रातः 11 बजे से चकबंदी अधिकारी प्रथम की उपस्थिति में ग्राम चौपाल आयोजित होगी। ग्राम कोहनकू में दिनांक 28 फरवरी को प्रातः 11 बजे से चकबंदी अधिकारी मुरादाबाद द्वितीय/ चतुर्थ की उपस्थिति में ग्राम चौपाल आयोजित होगी। इसी के साथ ग्राम सैजनी ऐहतमाली में 25 फरवरी को अपरान्ह 2 बजे से तथा ग्राम कांकरखेडा में दिनांक 26 फरवरी को अपरान्ह 2 बजे से चकबंदी अधिकारी मुरादाबाद तृतीय की उपस्थिति में ग्राम चौपाल का आयोजन होगा।

सामूहिक विवाह एवं परिचय सम्मेलन 28 को

मुरादाबाद। भारतीय संस्कृति रक्षा समिति एवं अर्द्धमौनी सर्व कल्याण ट्रस्ट द्वारा 28 फरवरी 2026 को रैड सैफायर, आशियाना, मुरादाबाद में विराट हिन्दू विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सत सनातन, जैन, सिख एवं बौद्ध सभी वर्गों के 251 युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन तथा 21 कन्याओं का कन्यादान भी किया जायेगा।सभी धर्म गुरुओं, सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारियों एवं राष्ट्र सेवा में लगे हुए भामाशाहों के द्वारा नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया जाएगा।इस समारोह का नाम स्वयंवर रखा गया है जिसमें परिचय के उपरांत विवाह के गठबंधन में बँधने जा रहे नव युगल के द्वारा अंतर्जातीय विवाह को भी बढ़ावा मिलेगा।इस संबंध में आहूत प्रेस वार्ता व बैठक की अध्यक्षता निर्यातक एवं समाजसेवी श्री राजेश रस्तोगी एवं सोमनाथ पोपली जी द्वारा व संचालन आचार्य धीरशान्त अर्द्धमौनी द्वारा किया गया।बैठक में कार्यक्रम संयोजक अरविंद अग्रवाल जॉनी , सरदार गुरविंदर सिंह , अनिल सिक्का द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। बैठक में सुधीर गुप्ता, संतोष नारंग, मीनू विज, सुधा शर्मा, शालिनी अग्रवाल, ममता चौधरी, सुनीता चौधरी, स्नेहलता चौधरी, शालिनी रस्तोगी, 'योति सिंह, सुगंध कपूर आदि रहे।

सपाईयों ने संत गाडगे को किया नमन

मुरादाबाद। संत गाडगे जयंती पर समाजवादी पार्टी ने सिविल लाइन्स स्थित कार्यालय में संत गाडगे जयंती पर सोमवार को सादगी और सम्मान के साथ मनाया सपा नेताओं ने स्व'छता और समाज सुधार के प्रणेता संत गाडगे को याद करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया। जिलाध्यक्ष जयवीर सिँह यादव संत गाडगे की चित्र पर माल्यार्पण कर नमन करतें हुए कहा गाडगे का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता और स्व'छता का संदेश देना था। गाडगे महाराज ने शिक्षा और स्व'छता के उपदेशों को रेखांकित किया। बाबा के जीवन और उनके विचारों का गुणगान किया गया, जिसमें अंधविश्वास के खिलाफ उनकी लड़ाई का जिक्र किया । संत गाडगे के दलितों और वंचितों के उत्थान के लिए किए। जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, महासचिव फुरकान अली, लाखन सिँह सैनी, वेदप्रकाश सैनी,आशकार पाशा,ब्रजलाल जाटव,दिलप्रीत सिँह, नागभारती, लुकमान खान, योगेंद्र यादव वाहन सिँह, कयामुद्दीन सैफी, मोहन यादव, बालकिशन शर्मा, शंकर लाल सैनी सरदार पाल, राजीव विश्नोई,सर्वेश प्रजापति,विनय प्रसाद, रोहित कुमर आदि उपस्थित रहे।

अधीनस्थ कृषि सेवा संघ वाराणसी मण्डल को मिला नया नेतृत्व

जय प्रकाश गुप्ता बनाये गये मण्डल अध्यक्ष, निर्विरोध हुआ चयन

रामपुर, जौनपुर।

अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले वाराणसी मंडल का अधिवेशन उप कृषि निदेशक कार्यालय वाराणसी के सभागार में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में सर्वसम्मति से संगठन के नये मण्डलीय पदाधिकारियों का चयन किया गया जिसमें जय प्रकाश गुप्ता (प्रान्तीय कोषाध्यक्ष) को वाराणसी मण्डल अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी सौंपी गयी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रान्तीय संगठन मंत्री डा. राजशेखर रहे एवं विशिष्ट अतिथि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी के अध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव उपस्थित रहे। अधिवेशन में विभिन्न जनपदों से

आए प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही। जौनपुर से अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव व मंत्री सकल नारायण पटेल, गाजीपुर से अध्यक्ष रजनीश पाल व मंत्री राकेश सरोज, चंदौली से कोषाध्यक्ष चंदन गुप्ता तथा जनपद वाराणसी से अध्यक्ष हेमलता भारतीय व मंत्री प्रियंका गुप्ता की उपस्थिति में यह निर्विरोध चयन सम्पन्न हुआ।

वाराणसी मण्डल के नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण

मण्डल अध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. विनोद सोनकर, मंत्री डा. भास्कर दुबे, संगठन मंत्री चन्दन गुप्ता, कोषाध्यक्ष रामहंस कुशवाहा हैं। चयन उपरान्त प्रान्तीय संगठन मंत्री डा. राजशेखर ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। इस मौके पर उन्होंने संगठन की एकता, कर्मचारियों के हितों की रक्षा तथा विभागीय समस्याओं के समाधान के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। अधिवेशन के समापन पर उपस्थित सदस्यों ने नवगठित मंडलीय टीम को बधाई देते हुये आशा व्यक्त किया कि नया नेतृत्व संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनायेगा।

सौरभ भारद्वाज का दिल्ली बेहाल जन संवाद, बोले- चार इंजन की सरकार में भी बेहाल हैं दिल्ली वाले

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने 'दिल्ली बेहाल जनसंवाद' कैंपेन के तहत निराश दिल्ली में बड़ी सभा कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. दिल्ली में हर मंडल पर दिल्ली बेहाल जनसंवाद चल रहे है. इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की चार इंजन की सरकार है फिर भी दिल्लीवाले बेहाल है. सरकार के एक साल बीत गए, लेकिन न महिलाओं को 2500 रुपए मिले और ना ही बस मार्शलों को पक्की नौकरी मिली. रेखा गुप्ता सरकार ने सिर्फ प्रदूषण कम करने, नकली यमुना बनाने और 370 मोहल्ला क्लीनिकों का नाम आरोग्य मंदिर करने का फर्जीवाड़ा किया. इन्होंने मोहल्ला क्लीनिकों को बंद कर हजारों युवाओं को बेरोजगार कर दिया और अब 6 हजार बस कंडक्टरों को निकाल रहे है. एक मार्च को आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर विशाल जनसभा कर बेहाल दिल्ली की जनता की आवाज उठाएगी.निराश दिल्ली में 'दिल्ली बेहाल जनसंवाद' के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही सेठ-साहूकारों और बड़े-बड़े धन्नासेठों की पार्टी रही है. ये लोग चुनाव के समय ही गरीबों के बीच आते है, झुग्गियों में रोटी खाते है और कैरम बोर्ड खेलते है. गरीब आदमी भोला होता है और इनकी बातों में आकर बेवकूफ बन जाता है. इस बार दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम और गरीब लोगों को बेवकूफ बनाया और 27 साल बाद इनकी दिल्ली में सरकार बन गई. ''आप'' सरकार ने बड़ी मुश्किल से गांवों के लिए जो सुविधाएं बनवाई थीं, बीजेपी ने आते ही उन्हें छीन लीं. गांवों व कस्बों में वह सोचकर डिस्पेंसरी बनवाई गई ताकि गरीबों और बुजुर्गों को आसानी से इलाज मिल सके.

सौरभ भारद्वाज ने शेख समय में पानी टंकी के नीचे बनाए गए मोहल्ला क्लीनिक में सबसे ज्यादा गांव की महिलाएं इलाज के लिए आती थी. महिलाएं पैसे व समय की कमी के कारण डॉक्टर के पास नहीं जा पाती है. ऐसे में मोहल्ला क्लीनिक में डायबिटीज, थायरॉइड और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों के फ्री टेस्ट और फ्री दवाइयां मिलने से उन्हें बहुत सुविधा हुई थी. लेकिन बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता एक- एक कर मोहल्ला क्लीनिकों को बंद कर रही है. सीएम ने 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का झूठा दावा कर रही है. असलियत में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के समय बनी डिस्पेंसरियों की रंगाई पुताई कर उस पर आरोग्य मंदिर लिखवा दिया है. यह खुल्लम-खुल्ला फर्जीवाड़ा और फ्रॉड है. कोठियों में रहने वाला आदमी सोचता है कि रेखा गुप्ता बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन गांव का आदमी सच्चाई जानता है, क्योंकि वह धरातल पर सब देख रहा है. बीजेपी ने एक साल में गांव के लिए कोई काम नहीं किया है. सीवर, चौपाल, सड़क के काम ''आप'' सरकार में पास कराए गए बजट से हो रहे है. सौरभ भारद्वाज ने बताया कि पिछले 8-9 सालों से ''आप'' सरकार दिल्ली के 360 गांवों के लिए शाहपुर जट गांव में एक शाहपुर जट फेस्टिवल करवाती थी. इसमें गांव के बुजुर्ग भी फैशन शो करते थे. लेकिन बीजेपी की विधायक ने यह फेस्टिवल बंद करवा दिया और उसे गांव से उठाकर ग्रेटर कैलाश की कोठियों में ले गई.

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को लिखा पत्र

अवैध घुसपैठ और महिला सुरक्षा समेत उठाए कई मुद्दे

नई दिल्ली।

पश्चिम बंगाल में आगामी राजनीतिक हलचलों के बीच पीएम मोदी ने बंगाल के नाम पत्र लिखा है। पीएम ने राज्य के मतदाताओं को बंगाली और हिंदी भाषा में एक पत्र लिखकर सीधा संवाद किया है। इस पत्र के जरिए पीएम ने एबार बीजेपी सरकार (इस बार भाजपा सरकार) का नारा देते हुए बंगाल की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और राज्य के कायाकल्प का संकल्प दोहराया है।

सोनार बंगाल का सपना और सुरक्षा पर सवाल

प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि सोनार बंगाल की चाह रखने वाला आज हर नागरिक दुखी है। उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहा कि बंगाल की माताएं और बहनें आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। पीएम के अनुसार, अवैध घुसपैठ और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा ने राज्य की छवि को धूमिल किया है। उन्होंने वादा किया कि वे बंगाल को एक विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

कल्याणकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड

पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने जनहित को ही सर्वोपरि रखा है। राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग न मिलने के बावजूद केंद्र ने बंगाल में बड़े स्तर पर काम किए हैं। जन-धन योजना के जरिए लगभग 5 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया और स्वच्छ भारत अभियान के तहत 85 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ।

भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि जब गरीबों का हक छीना जा रहा था, तब केंद्र ने छोटे व्यापारियों को 2.8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देकर सहारा दिया। उन्होंने गांव-गांव तक पहुँची बिजली, पानी और सड़कों को अपनी सरकार की नीतियों का सुखद परिणाम बताया।

मातृशक्ति पर भरोसा

अपने संदेश के अंत में पीएम ने महिलाओं के साहस की सराहना करते हुए कहा कि मेहनती महिलाएं ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। उन्होंने बंगाल के हर परिवार की खुशहाली और प्रगति की कामना करते हुए सम्मानजनक जीवन देने का भरोसा दिलाया।

पानीपत रिफाइनरी में सुरक्षा बलों पर पथराव, मजदूरों ने गाड़ियां तोड़ीं

सीआईएसएफ ने हवाई फायर किए; डेढ़ घंटे माहौल तनावपूर्ण रहा

पानीपत। (वेबवार्ता) पानीपत रिफाइनरी में सोमवार को मजदूरों ने अर्धसैनिक बलों पर पथराव किया। मजदूर ओवरटाइम, अधिकारियों के दुर्व्यवहार समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उनसे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की बात कही। इसके बाद, मजदूर लाठी-डंडों से लैस होकर आगे बढ़ने लगे। कुछ मजदूरों ने पथराव किया और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के पास खड़ी कई गाड़ियों को पलट दिया। वहां 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सीआईएसएफ अधिकारियों ने 2 हवाई फायर भी किए। घटना से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं। इसमें कई पुलिसकर्मी दौड़कर अपनी जान बचाकर भागते हुए दिख रहे हैं। मजदूर भी उनके पीछे दौड़ रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मियों के सिर में भी चोट लगी हुई दिख रही है। सूचना मिलते ही पुलिस भी रिफाइनरी पहुंच गई। पुलिस और सुरक्षा बल ने मिलकर माहौल को शांत करने की कोशिश की। करीब डेढ़ घंटे बाद मामला शांत हुआ।

करीब 40 हजार मजदूरों ने प्रदर्शन शुरू किया

रिफाइनरी के अंदर कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। यहां ठेकेदारों के अंतर्गत लगभग 35 से 40 हजार मजदूर अलग-अलग साइटों पर काम करते हैं। सोमवार को सभी मजदूरों ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। सुबह 9:30 बजे मजदूर गेट नंबर 4 के पास धरने पर बैठ गए। अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने।

सीआईएसएफ कर्मचारियों से कहासुनी के बाद बिगड़ा मामला

आरोप है कि दोपहर करीब 1 बजे रिफाइनरी में सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ कर्मचारियों और मजदूरों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद मजदूर भड़क गए। वे हाथों में लाठी-डंडे लेकर आगे की तरफ बढ़े और पथराव कर दिया। इसके बाद भीड़ ने वहां तोड़फोड़ की। सीआईएसएफ कर्मचारियों ने भी जवाब में 2 हवाई फायर किए। इसके बाद पुलिस कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया।

डीएसपी बोले- पुलिस ने व्यवस्था संभाली

डीएसपी सिटी राजबीर ने कहा कि मजदूरों ने कुछ मांगों को लेकर आज सोमवार को हड़ताल का ऐलान किया था। हड़ताल के दौरान यहां माहौल गर्म हो गया। मौके पर पुलिस ने कानून व्यवस्था को संभाल लिया है। साथ ही मजदूरों के पदाधिकारियों से बात की गई है। उन्होंने अपनी कुछ मांगें लिखित रूप में दी है। अभी माहौल शांतिपूर्वक है।

झारखंड के चतरा में एयर एंबुलेंस क्रैश- रांची से दिल्ली जा रही थी, विमान में 7 लोग सवार थे

रांची। झारखंड से दिल्ली जा रहा एक चार्टेड प्लेन चतरा में क्रैश हो गया। यह एक एयर एंबुलेंस थी। रेडबर्ड कंपनी के बीचक्राफ्ट किंग एयर C90 मेडिकल चार्टर फ्लाइट में क्रू मेंबर समेत सात लोग सवार थे। फ्लाइट ने सोमवार शाम 7:11 बजे रांची से उड़ान भरी, 7:34 पर एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन टूट गया। थोड़ी देर बाद प्लेन झारखंड के चतरा जिले के समरिया के जंगलों में क्रैश हो गया। प्लेन में कैप्टन विवेक विकास भगत (पायलट), कैप्टन सबराजदीप सिंह (को- पायलट), संजय कुमार (मरीज), अर्चना देवी (परिजन), धुरू कुमार (परिजन), विकास कुमार गुप्ता (डॉक्टर), सचिन कुमार मिश्रा (पारामेडिकल स्टाफ) सवार थे। चतरा के एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि क्रैश साइट जंगल में बहुत अंदर है। पुलिस टीम अभी मौके पर नहीं पहुंची है, इसलिए हादसे में कितने लोगों की जान गई। इसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे। रांची के देवकमल हॉस्पिटल के सीईओ, अनंत सिन्हा ने पीटीआई को बताया कि एयर एंबुलेंस का इंतजाम एक मरीज ने किया था। उन्होंने कहा, लातेहार जिले के चंदवा के रहने वाले मरीज संजय कुमार (41) को 16 फरवरी को 65 परसेंट जलने की हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। सिन्हा ने आगे कहा कि परिवार वालों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने का फैसला किया। मरीज लगभग 4.30 बजे हॉस्पिटल से दिल्ली के लिए निकला।

कोटद्वार के मोहम्मद दीपक की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात, गर्मजोशी के साथ गले लग किया स्वागत

देहरादून। कोटद्वार के मोहम्मद दीपक ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी गर्मजोशी के साथ दीपक के गले लगे। कोटद्वार पटेल मार्ग पर एक कपड़े की दुकान के नाम को लेकर उभरे विवाद के बीच मोहम्मद दीपक चर्चा में आया था। मामले में तब और तूल पकड़ा जब राहुल गांधी ने इसे लेकर ट्वीट किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संचार विभाग के सचिव वैभव वालिया के नेतृत्व में कोटद्वार के दीपक ने नेता विपक्ष राहुल गांधी से आज नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। वालिया ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोटद्वार के हमारे भाई दीपक कुमार को अपने आवास पर आमंत्रित कर उनसे आत्मीय मुलाकात की।

दीपक कुमार जो अपने मानवीय कार्यों और इंसानियत की मिसाल के रूप में देशभर में पहचान बना चुके है, से राहुल गांधी ने स्नेहपूर्ण संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन किया। यह मुलाकात केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि समाज में मानवता, करुणा और सेवा भाव की भावना का सम्मान है।

राहुल गांधी द्वारा दीपक कुमार जैसे प्रेरणास्रोत व्यक्तित्व को अपने घर पर आमंत्रित कर सम्मानित करना यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी सदैव उन लोगों के साथ खड़ी है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रहे हैं।

तमिलनाडु में मतदाता सूची में बड़ी छंटनी : एसआईआर के बाद 97 लाख नाम हटे, अब कुल मतदाता संख्या पांच करोड़ 43 लाख

चेन्नई। तमिलनाडु में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार (23 फरवरी 2026) को फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया है. राज्य में हुए एसआईआर में बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं. तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक के मुताबिक फाइनल मतदाता सूची से 7,40,7207 नाम हटा दिए गए हैं. इन नामों के हटाए जाने के बाद तमिलनाडु में मतदाताओं की कुल संख्या अब 5,67,07,380 हो गई है. एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले राज्य में 6,41,14,587 मतदाता रजिस्टर्ड थे. चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हटाए गए नामों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा मृत मतदाताओं का है. कई वजहों से नाम हटाए गए पात्र मतदाता फॉर्म-6 के जरिए फिर से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा 12,43,363 लोगों को नोटिस जारी किए गए, जिनके नाम में गलतियां थीं उनको भी वोटिंग लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने के लिए

निर्धारित समय के भीतर डॉक्यूमेंट और सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया गया.

चुनाव आयोग ने किया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन

चुनाव आयोग ने पुनर्विचार प्रक्रिया में 30 जनवरी के निर्देश का भी पालन किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जारी किया गया था. इसमें यह अनिवार्य किया गया था कि कॉन्ट्रोवर्सी या असंगत जानकारी के कारण नामों को हटाने के कारणों के साथ सार्वजनिक रूप से जारी किए जाएंगे. ये लिस्ट ग्राम पंचायत कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, ब्लॉक और सब डिवीजन कार्यालयों और शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालयों में जारी की गई.

आपत्ति दर्ज करने के लिए 10 दिन का समय

एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्रभावित व्यक्तियों को आपत्तियां दर्ज करने या स्पष्टीकरण के लिए 10 दिन का समय दिया गया है. एसआईआर से पहले राज्य में मतदाताओं की संख्या 6.41 करोड़ थी. इस बीच, एसआईआर के दूसरे चरण के दौरान 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 8 फीसदी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया गया. 14 फरवरी को प्रकाशित पुडुचेरी की अंतिम मतदाता सूची में कुल 9,44,211 मतदाता दर्ज किए गए.

HAL का दावा- तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ मामूली खराबी थी

नई दिल्ली। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सोमवार को इंडियन एयर फोर्स के फाइटर जेट तेजस के क्रैश की खबरों को गलत बताया है। HAL ने कहा है कि ग्राउंड पर एयरक्राफ्ट में मामूली तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। हवा में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। HAL ने बताया कि वह एयरफोर्स के साथ मिलकर तकनीकी गड़बड़ी की जांच कर रही है और उसे जल्द ठीक करेगी। कंपनी ने यह भी दावा किया कि तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया के आधुनिक फाइटर जेट्स में सबसे बेहतर में से एक है। न्यूज एजेंसी ने रविवार देर रात सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि 7 फरवरी को तेजस लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया था। PTI के मुताबिक, फाइटर जेट ट्रेनिंग उड़ान के बाद एयरबेस पर लौट रहा था। लैंड करते ही पायलट ने ब्रेक लगाने की कोशिश की। जब ब्रेक नहीं लगा तो विमान रनवे से आगे निकल गया। हालांकि हादसे से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया लेकिन विमान को नुकसान पहुंचा है। शुरुआती जांच में ब्रेक फेल होने की आशंका जताई गई है। हालांकि, हादसा किस एयरबेस पर हुआ, PTI ने इसकी जानकारी नहीं दी।

लाल किला, विधानसभा और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सर्च अभियान के बाद निकली अफवाह

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के धौला कुआं में आर्मी पब्लिक स्कूल और लोधी रोड पर एयर फोर्स बाल भारती स्कूल को एक ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली विधानसभा, दिल्ली सचिवालय और लाल किले को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस धमकी भरे ई-मेल के प्राप्त होते ही स्कूल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तत्काल कार्रवाई करते हुए, स्कूल परिसर को खाली करा लिया गया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गहन जांच की। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद दोनों स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेशन ने सुबह अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। जानकारी के अनुसार, स्कूल प्रशासन को एक अज्ञात ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। ई-मेल मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर पूरे स्कूल परिसर को खाली कराया और चप्पे-चप्पे की तलाशी शुरू कर दी। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को

बाहर निकाला गया। ई-मेल के जरिए दिल्ली विधानसभा और लाल किला को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, दो स्कूलों, आर्मी पब्लिक स्कूल, धौला कुआं और एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड को ईमेल से बम की धमकी मिली थी। एहतियात के तौर पर जगह खाली करा ली गई और पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया।

जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला

जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बारीकी से जांच की गई, लेकिन बम या विस्फोटक जैसी कोई चीज बरामद नहीं हुई। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सचिवालय, दिल्ली विधानसभा, लाल किला और देश की राजधानी के दो स्कूलों समेत कई संस्थानों को सोमवार को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली। जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई, जिसके बाद इसे होक्स कॉल यानी झूठी धमकी करार दिया गया।

गुरुग्राम के एयर फोर्स स्कूल को भी खाली कराया

गुरुग्राम के राजीव चौक स्थित एयर फोर्स स्कूल को एहतियातन खाली कराया गया। धमकी वाले ई-मेल में किसी स्कूल का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सुरक्षा सतर्कता के चलते गुरुग्राम के एयर फोर्स स्कूल को भी खाली कराया गया।

गुजरात में अतिक्रमण हटाओ अभियान- राजकोट में 1400 से अधिक अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

राजकोट। गुजरात के राजकोट शहर के जंगलेश्वर क्षेत्र में सोमवार से अवैध कब्जा हटाने का एक बड़ा अभियान शुरू हो गया है। राजकोट महानगरपालिका (आरएमसी) यहां 1,489 अवैध मकानों और इमारतों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के आदेश मिलने के बाद शुरू की गई है। नगर निगम की टीम अजी नदी के किनारे और टाउन प्लानिंग (टीपी) रोड से अतिक्रमण हटा रही है। इस अभियान के तहत लगभग 87,000 वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया जाएगा। सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भक्तिनगर सर्कल के पास सेठ हाई स्कूल में 2,500 से ज्यादा निगम अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। निगम ने शनिवार से ही लोगों से घर खाली करवाना शुरू कर दिया था।

क्या बोले अधिकारी?

म्युनिसिपल कमिश्नर तुषार सुमेरा ने बताया कि नदी किनारे और सड़क पर हुआ निर्माण पूरी तरह अवैध है और इसे हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम की टीम पिछले

पांच दिनों से घर-घर जाकर लोगों को समझा रही थी। प्रशासन ने लोगों को अपना सामान ले जाने के लिए ट्रैक्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। मौके पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और वे खुद पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। राजकोट के डीसीपी क्राइम जगदीश बगरवा ने बताया कि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। समझाने की वजह से कई लोगों ने खुद ही अपना कब्जा हटा लिया था।

क्या बोले लोग?

हालांकि, प्रशासन के इस कदम से वहां दशकों से रह रहे लोगों में काफी गुस्सा है। जंगलेश्वर गली नंबर तीन के रहने वाले हारूनभाई सुमरा ने बताया कि वे 43 साल से इस इलाके में रह रहे हैं। वे और उनकी बहन दोनों दिव्यांग हैं और मजदूरी करके पेट पालते हैं। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ दो दिन पहले बताया गया कि हमारा घर गिरा दिया जाएगा। अब हम कहां जाएंगे? हमें शायद सड़कों पर रहना पड़े। वहीं, एक अन्य निवासी हलिमबेन ने कहा कि उनका परिवार 50 साल से यहां रह रहा है और उन्हें घर खाली करने का आदेश मिला है। उन्होंने कहा, आठ लोगों के परिवार को कोई भी किराए पर घर देने के लिए तैयार नहीं है। हम सड़क पर रहने की तैयारी कर रहे हैं।

अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने की भीषण बमबारी, बुरी तरह भड़का भारत!

नई दिल्ली।

अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हालिया स्ट्राइक ने दोनों देशों के बीच तनाव को फिर से चरम पर पहुंचा दिया है। दोनों देश अब आमने-सामने हैं और इसी बवाल के बीच भारत भी तालिबान के समर्थन में कूद पड़ा है। भारत ने ना केवल इन हमलों की निंदा की बल्कि पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। भारत ने इसे पाकिस्तान की घरेलू विफलताओं से ध्यान भटकाने की एक हताश कोशिश करार दिया है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान द्वारा किए गए इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत आम नागरिकों की मौत होना बेहद निंदनीय है। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अपने आंतरिक समस्याओं और सुरक्षा मोर्चे पर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पड़ोसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है।

भारत ने एक बार फिर दोहराया कि वो अफगानिस्तान की सोवरिनिटी यानी संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान इस हमले के बाद अब सफाई देने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने इस कार्रवाई का

बचाव किया है। इस्लामाबाद का दावा है कि उसने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अफगानिस्तान के भीतर तहरीक तालिबान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट आईएसपी के सात ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि बन्नू और बजौर में हुए आतंकी हमलों के तार अफगान हैंडलर से जुड़े थे। जिसके जवाब में यह कार्रवाई जरूरी थी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर आरोप लगाया कि बार-बार चेतावनी के बावजूद काबुल अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी आतंकियों को करने से रोकने में नाकाम रहा है। लेकिन काबुल ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

अफगान रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को अंतरराष्ट्रीय कानून और देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। साथ ही उचित और सोच समझकर जवाब देने की चेतावनी भी दी है। अफगानिस्तान का कहना है कि उसकी जमीन और नागरिकों की रक्षा करना उसका धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है।

दरअसल पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के रिश्तों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इस्लामाबाद का आरोप है कि काबुल अपनी जमीन से संचालित पाकिस्तान विरोधी आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं करता।